(ग) क्या सरकार संसद स्दस्यों व महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच किसी उच्च अधिकारी अथवा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से कराने का विचार रखती है; यदि हां, तो इस संबध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) इंदरीज पुत्र श्री काजिल अली (न कि मोहम्मद कासिम) निवासी झुग्गी ठेका शराब, बुलंद मस्जिद द्वारा एक सहायक उप निरीक्षक के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है । सहायक पुलिस आयुक्त सीलमपुर को मामले की जांच पड़ताल करने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है। महत्वपूर्ण शिकायतों की जांच पड़ताल सतकर्ता, शाखा द्वारा की जाती है जो सीधे पुलिस आयुक्त के पर्यवेक्षण में कार्य करता है ।

Bodo students' demand for separate state of Bodoland

1916. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government of India has been drawn to the news item published on December 30, 1989 in the Times of India under the caption "Bhutan paid for Bodo areas";

(b) whether it is **a** fact that India is paying Rs. 5 lakhs to Bhutan for part of Bodoland;

(c) whether it is a fact that Dewangiri territory of Bodoland has been given to Bhutan; and

(d) what is the reaction of Go vernment on the demand of Bodo Student's Union for a separate State of Bodoland?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I. K. GUJ-RAL): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No Sir. Dewangiri was originally part of Bhutan and was captured by the British in 1864 during the Anglo-Bhutan war. Under Article IV of the Treaty of Sinchula, Govt, of Bhutan ceded Dewangiri, along with other areas to the British Government. The latter agreed to pay an annual compensation for these areas. Under Article III of Indo-Bhutan Treaty of 1949, the Govt, of India agreed to make an annual payment of Rs. 5 lakhs in place of the compensation granted under the Treaty of Sinchula.

In response to repeated requests from the Government of Bhutan, the Govt, of India, under Article IV of the Indo-Bhutan Treaty of 1949, agreed to the return of Dewangiri to Bhutan to underline the friendship existing and continuing between the two Governments.

(d) the Government of India, on several occasions, have reiterated that it was not in favour of any further division of Assam. They are extending all necessary help and cooperation to the State Government of Assam for solving the problems of the Bodo/Plan Tribals.

Punjabi films televised by the Doordarshan

1917. SHRI SOHAN LAL DHUSIYA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the number of Punjabi films televised by Doordarshan during the last three years;

(b) whether the number of Punjabi films exhibited is less in comparison to the other regional language films; and

(c) whether Govarnment propose to increase the number of Punjabi films to be televised in the near future and if so, the number of films selected for the purpose during the year 1990-91?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA): (a) to (c) Doordarshan has telecast 44 Punjabi feature films during the last three years. It is not appropriate to compare this figure with that of other regional language films as their telecast depends upon such factors as the number of offers made and their acceptability as per the eligibility criteria.

The yearly schedule of films to be telecast is not prepared by Doordarshan.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिल्ली में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के साथ कथित दुर्व्यवहार

1918. श्री अजीत जोगी :
श्री लोहत लाल थुसिया :
श्री राम सिंह राठवा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें दिल्ली में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री एस०एम० अग्रवाल के साथ दुर्व्यवहार किया था और जिसके फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के वकीलों ने हड़ताल कर दी थी ;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त न्यायाधीश ने अपने बयान में इस बात का उल्लेख किया है कि इस तरह की घटनाओं से पुलिस आयुक्त प्रणाली के अधीन पुलिस की निरंकुशता प्रमाणित होती है तथा क्या उनकी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस प्रणाली की समीक्षा करने और पुलिस को कार्यकारी न्यायाधीशों के अधीन रखने की पूर्ववर्ती कार्य प्रणाली लागू करने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 7-3-1990 को दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त और अपर सत्र न्यायधीश के बीच एक अप्रिय घटना घटी । उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के वकीलों ने 9-3-90 को एक दिन की हड़ताल की ।

(ख) और (ग) अपर सत्र न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सहायक पुलिस आयुक्त के खिलाफ एक अवमानना याचिका दायर की है जो लम्बित है। मामला न्यायाधीन है ।

Tripura-Bangladesh border

1919. SHRI NARAYAN KAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many kilometres the Tripura-Bangladesh border measure and how many B.S.F. Battalions have been engaged on the border;

(b) how many kilometres the Assam-Bangladesh border measures and how many B.S.F. Battalions have been engaged in the border;

(c) whether it is a fact that so far not even a jeepable road has been built along the Tripura-Bangladesh border adjascent to Chictagong and that proposed observation tower also has not been built on that border; and